ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 8, August 2017

भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ

डॉ. राजकुमार गोयल

सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राज.)

सार

1947 में भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक विश्व व्यापक रूप से बदल चुका है। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के द्विध्रुवीय विश्व से लेकर अमेरिकी आधिपत्य के एक संक्षिप्त एकध्रुवीय काल तक और अब चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विध्रुवीय प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ने से लेकर बहुध्रुवीयता के एक भ्रम तक विश्व ने कई स्वरुप देखे हैं।आज के इस विशृंखल विश्व में भारत को अपनी विशिष्ट विदेश नीति पहचान को परिभाषित करने और नैतिक मूल्यों के साथ राष्ट्रीय हित को संतुलित करने के लिये अपनी संलग्नता की रूपरेखा को आकार देने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट (State) या राज्य में चार तत्त्व होते हैं- जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता।जबकि नेशन (Nation) या राष्ट्र साझा जातीयता, इतिहास, परंपराओं और आकांक्षाओं पर आधारित एक समुदाय होता है।एक वैधानिक निकाय के रूप में राज्य अपने लोगों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिये उत्तरदायी है और यह बाह्य मानवीय कार्यकरण से संबंधित है।जबकि राष्ट्र उन लोगों का एक निकाय होता है जो भावनात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से एकजुट होते हैं।क्षेत्र (Territory) भी राज्य का एक अनिवार्य अंग होता है, क्योंकि यह राज्य का भौतिक तत्त्व होता है।लेकिन एक राष्ट्र के लिये, क्षेत्र इसका अनिवार्य अंग नहीं है। राष्ट्र एक निश्चित क्षेत्र के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है।अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में राज्य में कई राष्ट्र शामिल हैं और इस प्रकार वे 'बहुराष्ट्रीय समाज' (Multinational societies) हैं।

परिचय

'इंडिया फर्स्ट' की नीति: स्वतंत्रता के 75 वर्षों के साथ देश में 'इंडिया फर्स्ट' की विदेश नीति को अभिव्यक्त करने का वृहत आत्म-विश्वास और आशावाद मौजूद है। भारत अपने लिये स्वयं निर्णय लेता है और इसकी स्वतंत्र विदेश नीति किसी भयादोहन या दबाव के अधीन नहीं लाई जा सकती।विश्व की लगभग 1/5 आबादी के साथ भारत को अपना स्वयं का पक्ष चुनने और अपने हितों का ध्यान रखने का अधिकार है।यह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक मूल तत्त्व है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और भारत ने भी अन्य देशों की तरह विदेशी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के अनुपालन में अपने हितों पर बल दिया है।यथार्थवादी कूटनीति: आज के आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत के पास वैश्विक फलक पर अपनी नई आवाज़ है जिसकी जड़ें घरेलू वास्तविकताओं एवं सभ्यतागत लोकाचार में निहित होने के साथ ही स्वयं के प्रमुख हितों की खोज में गहराई से जमी हैं।जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री ने 'रायसीना डायलॉग' में टिप्पणी की थी कि "विश्व को खुश करने की कोशिश करने के बजाय 'हम कौन हैं' के आधार पर विश्व से संलग्न होना बेहतर है।"[1,2] भारत अपनी पहचान और प्राथमिकताओं को लेकर पर्याप्त आत्म-विश्वास रखता है, दुनिया भारत के साथ इसकी शर्तों पर संलग्न होगी।अपने लाभ के लिये शक्ति संतुलन बनाए रखना: चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल को वर्ष 2014 में ही चुनौती दे देने वाली एकमात्र वैश्विक शक्ति होने से लेकर एक मज़बूत सैन्य कार्रवाई के साथ चीनी सैन्य आक्रमण का जवाब देने वाले देश के रूप में भारत ने दृढ़ता का परिचय दिया है।

दूसरी ओर, भारत ने किसी औपचारिक गठबंधन में शामिल हुए बिना ही अमेरिका के साथ एक कार्यकरण संबंध का विकास किया है और घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिये पश्चिमी देशों से संलग्नता बढ़ाई है।भारत संलग्नता में अत्यंत व्यावहारिक रहा है और शक्ति के मौजूदा संतुलन का उपयोग अपने लाभ के लिये करने की इच्छा रखता है।बढ़ते आर्थिक संबंध: चूँकि शेष विश्व के साथ भारत की आर्थिक अन्योन्याश्रयता गहरी होती गई है, यह अपने उत्पादों, कच्चे माल के स्रोतों और इसके विस्तारित विदेशी सहायता के संभावित प्राप्तकर्त्ताओं के लिये बाज़ारों के प्रति अधिक चौकस हो गया है।बहु-संरेखित/बहुपक्षीय दृष्टिकोण: चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड/Quad) से लेकर ब्रिक्स (BRICS) तक, भारत कई समूहों की सदस्यता रखता है।प्रायः इसे पुरानी शैली की संलग्नता के रूप में देखा जाता है। हालाँकि भारत अपनी प्राथमिकताओं को अधिक प्रत्यक्ष तरीके से अभिव्यक्त और प्रोत्साहित करने लगा है।हस्तक्षेप और अनुचित हस्तक्षेप: भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप (Iinterference) में विश्वास नहीं करता है।हालाँकि, यदि किसी देश द्वारा किये गए किसी सायास या निष्प्रयास कार्यकरण में भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने की क्षमता है तो भारत त्वरित और समयबद्ध हस्तक्षेप (Intervention) करने में संकोच नहीं करता है।भारत की विदेश नीति के नैतिक पहलू-पंचशील (Five Virtues): 29 अप्रैल, 1954 को हस्ताक्षरित 'चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के के बीच व्यापार

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 8, August 2017

समझौते' में पहली बार व्यावहारिक रूप से 'पंचशील' के सिद्धांत को अपनाया गया था, जो बाद में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिये आचरण के आधार के रूप में विकसित हुआ।ये पाँच सिद्धांत हैं:

- एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिये परस्पर सम्मान
- परस्पर गैर-आक्रामकता
- परस्पर गैर-हस्तक्षेप
- समानता और पारस्परिक लाभ
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

- वसुधैव कुटुम्बकम् (The World is One Family): 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भारतीय दर्शन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की अवधारणा को आधार प्रदान करता है।दूसरे शब्दों में, भारत संपूर्ण विश्व समुदाय को एकल वृहत वैश्विक परिवार के रूप में देखता है, जहाँ इसके सदस्य सद्भाव से रहते हैं, एक साथ कार्य एवं विकास करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं।सक्रिय और निष्पक्ष सहायता: भारत जहाँ भी संभव हो, लोकतंत्र को बढ़ावा देने में संकोच नहीं करता है।यह क्षमता निर्माण और लोकतंत्र की संस्थाओं को सशक्त करने में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करने के रूप में किया जाता है, यद्यपि ऐसा संबंधित सरकार की स्पष्ट सहमति से किया जाता है (उदाहरण के लिये अफगानिस्तान)।[3,4]वैश्विक समस्या समाधान दृष्टिकोण: भारत विश्व व्यापार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, वैश्विक शासन, स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक बहस एवं वैश्विक सहमति की वकालत करता है।'वैक्सीन डिप्लोमेसी' पहल के तहत भारत ने 60 मिलियन खुराक का निर्यात किया, जिनमें से आधे वाणिज्यिक शर्तों पर और 10 मिलियन अनुदान के रूप में प्रदान किये गए।

आंतरिक चुनौतियाँ: कोई देश बाह्य विश्व में शक्तिशाली नहीं हो सकता यदि वह घरेलू स्तर पर दुर्बल है।भारत का 'सॉफ्ट पावर' तब उपयोगी होगा जब इसे 'हार्ड पावर' का समर्थन प्राप्त होगा।भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बार-बार ज़ोर देते हुए कहा था कि भारत विश्व मंच पर तभी प्रभावी भूमिका निभा सकता है जब वह आंतरिक और बाह्य, दोनों रूप से सशक्त हो।शरणार्थी संकट: वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्षकार नहीं होने के बावजूद भारत विश्व में शरणार्थियों के सबसे बड़े स्थल वाले देशों में से एक रहा है।यहाँ चुनौती मानवाधिकारों और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण को संतुलित करने की है। रोहिंग्या संकट के उभार के साथ प्रकट है कि समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिये भारत द्वारा अभी भी बहुत कुछ किया कर सकता है।ये कार्रवाइयाँ मानवाधिकार के मामलों पर भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिये सामूहिक दृष्टिकोण: भारत में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता है, जो वर्ष 2070 तक 'नेट ज़ीरो' तक पहुँचने के लक्ष्य आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में घोषित) में परिलक्षित होती है।पर्यावरणीय समस्याएँ सामाजिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक, आर्थिक और साथ ही पारिस्थितिक स्तर पर संवहनीयता प्राप्त करने की आवश्यकता है जैसा कि सतत् विकास लक्ष्यों में रेखांकित किया गया है।आंतरिक और बाह्य विकास को संतुलित करना: भारत को एक बाह्य वातावरण के निर्माण के लिये प्रयास करना चाहिये जो भारत के समावेशी विकास के अनुकूल हो, ताकि विकास का लाभ देश के निर्धनतम व्यक्ति तक पहुँच सके।यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए और भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण,[5,6] वैश्विक शासन से संबद्ध संस्थानों के सुधार जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर विश्व के विचार को प्रभावित करने में सक्षम हो।विदेश नीति में नैतिक मूल्यों का प्रवेश कराना: महात्मा गांधी ने कहा है कि सिद्धांत और नैतिकता से रहित राजनीति विनाशकारी होगी। भारत को नैतिक अनुनय के साथ सामूहिक विकास की ओर बढ़ना चाहिये और विश्व में अपने नैतिक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिये।बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने के साथ-साथ नीति विकास: हम एक गतिशील दुनिया में रह रहे हैं। इसलिये भारत की विदेश नीति को सक्रिय एवं लचीला होने के साथ ही व्यावहारिक होना होगा ताकि उभरती परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया के लिये इसका त्वरित समायोजन किया जा सके।हालाँकि अपनी विदेश नीति के कार्यान्वयन में भारत हमेशा बुनियादी सिद्धांतों की एक शृंखला का पालन करता है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाता। ये बुनियादी सिद्धांत हैं:

- राष्ट्रीय आस्था और मूल्य

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 8, August 2017

- राष्ट्रीय हित
- राष्ट्रीय रणनीति

वैश्विक एजेंडा को आकार देना: भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक 'अग्रणी शक्ति' के रूप भूमिका निभा सकने की संभावनाओं का पता लगाना महत्त्वपूर्ण है, जो कि वैश्विक मानदंडों और संस्थागत वास्तुकला को आकार दे सके, न कि इन्हें दूसरों द्वारा आकार दिया जाए और भारत बस अनुपालनकर्त्ता हो।संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की आकांक्षा इसी भूमिका से संबद्ध है, जिसके लिये बड़ी संख्या में देशों ने पहले ही समर्थन देने का वादा कर रखा है।विकास के लिये कूटनीति: अपने विकास प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने के लिये भारत को पर्याप्त बाह्य आदान/इनपुट की आवश्यकता है।मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, अवसंरचना विकास, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया जैसे हमारे कार्यक्रमों की सफलता के लिये विदेशी भागीदारों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण की आवश्यकता है।भारत की विदेश नीति को विकास के लिये कूटनीति के इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जहाँ आर्थिक कूटनीति को राजनीतिक कूटनीति के साथ एकीकृत किया जाए।

विचार-विमर्श

भारत में नई सरकार के पदार्पण के साथ ही भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ में कई तरह के कयास लगने लगे. प्रश्न उठने लगे कि क्या भारतीय विदेश नीति में कुछ विशेष परिवर्तन किया जाएगा जो विदेश नीति का नया मानदंड या पर्याय बन जाएगा? एन डी ए सरकार के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या होंगी? उन चुनौतियों का सामना करने का सरकार का तरीका क्या होगा? इन प्रश्नों के साथ यह अनुमान भी लगाया जाने लगा कि विगत वर्षों में, विदेश नीति में जो एक ठहराव आ गया था, कम से कम उसमें कुछ गति आएगी. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआत करते हुए विश्व पटल पर भारत की छवि को मजबूत किया है. हालाँकि पड़ोस की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और अंतराष्ट्रीय स्तर पर विश्व ताकतों की नीतियों के मद्देनज़र एन डी ए सरकार की शुरुआती सफलता से बँधी उम्मीदों को बनाए रखना मुख्य चुनौती होगी.[7,8]

पिछले कुछ वर्षों में विश्व पटल पर होने वाली घटनाओं पर अगर ध्यान डाला जाए तो मुख्य चुनौतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं. दक्षिण एशिया, विशेषकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस वर्ष भारतीय विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं. सरकार ने 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति अपनाते हुए दक्षिण एशिया में एक अच्छी शुरुआत तो की, परन्तु अपनी इच्छा को ठोस परिणामों में परिवर्तित न कर सकी. पड़ोसी देशों के सन्दर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कदम बांग्लादेश के साथ 'सीमा समझौता' है. किन्तु दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा 'तीस्ता रिवर वॉटर' पर अभी तक कोई राय नही बन पाई है. चीनी पनडुब्बी के कोलंबो दौरे से जहाँ भारत और श्री लंका के रिश्तों में खटास आ गयी थी, वहीं नई सरकार मैत्रीपाला सीरीसेना के आगमन से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के अवसर बन गये हैं. यह देखना रोचक होगा कि नयी सरकार कैसे इस रिश्ते को आगे ले जाती है. भारत-पाकिस्तान के संबंधों में आए ठहराव के बाद नई दिल्ली को, चीन तथा अन्य बाहरी ताकतों के प्रभाव को संतुलित करते हुए, इस्लामाबाद के साथ सकारात्मक घटनाक्रम पर सावधानी से चलना होगा. वर्तमान परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ संबंधों में कोई बड़ी उपलब्धि दिखाई नहीं देती है परन्तु भारत को यह ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अफगानिस्तान पर भी प्रभाव डालेंगे. अफगानिस्तान से नाटो शक्तियों की वापसी के बाद क्षेत्रीय ताकतों ने अपना प्रभाव जमाने की कवायद शुरू कर दी है. अफगानिस्तान में अपनी पैठ प्रभावी ढंग से बनाए रखना नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. दक्षिण एशिया में आतंकवाद का मुकाबला करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होगा.

पश्चिम एशिया में होने वाली राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद की घटनाओं ने विश्व स्तर पर विषम परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं. पश्चिम एशिया में जिस तरह से इस्लामिक राज्य की घोषणा हुई है और जिस तरह विभिन्न देशों के युवा इस संगठन से जुड़ रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है. पश्चिम एशिया में तेल से होने वाली आय से इस्लामिक राज्य को समर्थन मिलने की संभावना है जिससे धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा मिलेगा. यह देखना स्वाभाविक होगा कि लीबिया, येमन, सिरिया और इराक़ जैसे राष्ट्र, जो विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा. इस्राइल और फ़िलिस्तीन जैसे मुद्दों को एक साथ कैसे संबोधित किया जाए. इस परिपेक्ष में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि तेल का आयात बिना बाधित हुए भारत पश्चिम एशिया की समस्याओं पर क्या रुख़ ले सकता है. साथ ही यह भी देखना होगा कि वहाँ काम कर रहे भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान न हो. एन डी ए सरकार को इस बात का ख्याल रखना होगा कि भारतीय संसाधनों के आतंकवादी संगठन द्वारा इस्तेमाल पर कैसे रोक लगाई जाए ताकि ऐसे आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ लामबंद ना हो पाएं.
भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है चीन के साथ अपने संबंधों की दिशा निर्धारित करना. चीन की प्रसारवादी नीति और आक्रामक रवैये से विश्व स्तर पर असहजता बढ़ी है. चीन, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को पूरी तरह से

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 8, August 2017

अपने प्रभाव का क्षेत्र मानता है. चीन अपने सामरिक और राष्ट्रीय हितों के लिए जो आक्रामक रवैया अपना रहा है, उसने जापान और विएतनाम जैसे देशों में असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है. इन्हीं वजहों से अमेरिका को विएतनाम और जापान जैसे देशों के साथ संबंध स्थापित करने में आसानी हो गयी है. जापान ने अपनी शांति समर्थन करने वाले संविधान में परिवर्तन कर, खुद को चीन की चुनौती के लिए तैयार करने की ठान ली है. भारत-चीन की सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से भारत में भी असहजता और चिंता की स्थिति है. हालाँकि गौरतलब है कि चीन भारत जैसे बाज़ार को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता है. भारत को यह निर्धारित करना है कि वो चीन के साथ सहयोग की नीति अपनाना चाहता है या अमेरिका के 'चीन की चुनौती' रोकने के अभियान में शामिल होना चाहता है. इसी संबंध में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिंताओं से चीनी राष्ट्रपति को अवगत कराया था. उन्होने ये भी कहा था कि भारत चीन के संबंध में संभावनायें तो बहुत हैं, मगर चुनौतियाँ भी उतनी ही हैं. संभावनायें व्यक्त की जा रहीं हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा कर सकते हैं. इस सन्दर्भ में चीन और अमेरिका के साथ संबंधों का निर्धारण भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.[9,10]

रूस और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना भी भारतीय विदेश नीति के लिए एक मुख्य मुद्दा होगा. अमेरिका ने भारत के 'रणनीतिक साझेदार' के रूप में पिछले दो वर्षों से, सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की जगह ले ली है. शीत युद्ध के बाद राष्ट्रीय हितों को पुनः परिभाषित करना, इसकी मुख्य वजह रही है. रूस और अमेरिका में 'युक्रेनिअन संकट' को लेकर जो सामयिक गतिरोध पैदा हुआ है उससे भारत के उपर भी दबाव बढ़ा है. 26 जनवरी 2015, को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मुख्य अतिथि के रूप में, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा कई मायनों मे महत्वपूर्ण है. इस यात्रा से भारत और अमेरिकी संबंधों मे एक नया दौर आया और 'आण्विक समझौते' में गतिरोध ख़त्म होने के आसार नज़र आने लगे. साथ हीं रक्षा सहयोग, विशेषकर रक्षा उत्पादन और रक्षा उपकरण के आयात को सुगम ब्राने की कोशिश की गयी. व्यापार और पेटेंट जैसे मुद्दों पर भी सकारात्मक बहस हुई. दूसरी ओर भारतीय और रूसी नेताओं के मुलाकात, विशेषकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के समय, रूस को ये आश्वासन दिया गया की रूस आगे भी भारत का हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहेगा. वर्तमान समय में इन दोनों देशों के बीच पुनः शीत युद्ध की स्थिति बनने से भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह क्या रुख़ अपनाता है और इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध कौन सी दिशा लेते हैं? यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को और कितनी गहराई तक ले जाया सकता है, यह भी विदेश नीति का एक मुख्य पहलू होगा. यूरोपीय देश भारतीय बाज़ार की ओर आकर्षित हैं, परन्तु 'मुक्त व्यापार क्षेत्र' के संबंध में जो वार्ता हो रही है वो किसी निश्चित दिशा की ओर नहीं जा रही है. भारत और यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार नई संभावनाओं को जन्म देगा.

यह माना जाता है कि भारत की विकास की गति, उसकी आर्थिक नीति व सामरिक सोच के कारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अवहेलना नहीं की जा सकती. इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशना और निर्यात को बढ़ावा देना भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण कदम होगा. भारत को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि विदेशों में अपने संसाधनों को और वृहत कैसे बनाया जाए. क्षेत्रीय सहयोग संगठनों जैसे दक्षेस और आसियान में भारत को अपनी भूमिका और सशक्त बनानी होगी और सबके साथ शांति और सहयोग के साथ आगे बढ़ने का संदेश देना होगा.

परिणाम

देशों की विदेश नीतियों के रणनीतिक उद्देश्य तथा भौगोलिक निर्देश अंतरराष्ट्रीय संवाद की रूपरेखा को मोटे तौर पर परिभाषित करते हैं। फिर भी विदेश नीति लगातार बदलती और दुरुस्त होती रहती है। उसे घरेलू बाध्यताओं तथा वैश्विक संपर्क की संभावनाओं एवं क्षमताओं के अनुसार और भी दुरुस्त किया जाता है ताकि उसके राष्ट्रीय हितों को तत्कालीन सरकार की धारणा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से साधा जा सके। भारत भी अपवाद नहीं है और गुट निरपेक्षता हो या प्रमुख शक्तियों को चुनकर उनके साथ गठबंधन करना हो, राष्ट्रीय हित के मामलों तथा विदेश नीति के मूल उद्देश्य पर आजादी के बाद से अभी तक समूचे राजनीतिक वर्ग का एकसमान मत रहा है। छोटे या लंबे समय में संभावित लाभों के मुताबिक परिवर्तन किए गए हैं। किंतु मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तासीन होने के बाद से विदेश नीति में विस्तार की शैली, तरीकों तथा घटकों में नाटकीय परिवर्तन हुआ है। इसके परिणामों से कुछ लोग असहमत हो सकते हैं किंतु परिवर्तन सामने दिख रहे हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने "इंडिया फर्स्ट" को सारगर्भित तरीके से विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य बना दिया और अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस नेताओं को न्योता देकर "पड़ोस" को प्राथमिकता देते हुए संपर्क आरंभ किया, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने उत्कृष्ट और असाधारण लेकिन आवश्यक शुरुआत का नाम दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अनुसार 170 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों के साथ इस दौरान बातचीत की गई।[11,12] क्षेत्रीय तथा वैश्विक मामलों में और अधिक प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे भारत जैसे देश के लिए अहम है कि उसे पड़ोसी देशों से सहयोग मिलता रहे। कोई और रास्ता ही नहीं है क्योंकि कोई भी अपने पड़ोसी चुन नहीं सकता, वे तो भूगोल तथा इतिहास से उसे मिलते हैं। हमारे मामले में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के बावजूद प्रयास

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 8, August 2017

जारी रहने चाहिए।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सद्भावना भरी कूटनीति दिखाए जाने अथवा बहुचर्चित 'सर्जिकल स्ट्राइक' या आतंकवाद पर नोटबंदी का कथित असर होने के बावजूद पाकिस्तान ने और हमले किए हैं, यह जानते हुए भी हमारा रुख अभी तक यही रहा है।नीति निर्माता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करना और उसे अलग-थलग करना चाहते थे। हालांकि इसमें कुछ सफलता मिलने का दावा किया जा सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान को उसके कुत्सित इरादों से तथा भारत विरोधी हमलों एवं गतिविधियों में लिप्त रहने से रोकने के लिए काफी नहीं रहा है। उल्टे पाकिस्तान ने विशेष रूप से तालिबान से घिरे अफगानिस्तान के संदर्भ में रणनीतिक रूप से अपनी बेहतर स्थिति का पहले अमेरिका तथा पश्चिम और अब रूस से लाभ उठाया है।चीन भी हर मुश्किल में उसका दोस्त बना रहा है और वैश्विक चिंताओं को नजरअंदाजा कर हर परिस्थिति में पाकिस्तान का साथ निभाता रहा है। हमारे अन्य पड़ोसी भी अक्सर क्षेत्रीय ताकतों विशेषकर चीन से अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए दांव खेलते रहते हैं। उनके राष्ट्रीय हितों के लिहाज से देखा जाए तो ऐसी अस्थिर कूटनीति समझ में आती है, लेकिन इसके फेर में हमारी सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों से समझौता हो जाता है। इस उपक्षेत्र में भारत को दबाकर रखने अथवा नीचा दिखाने की इच्छा वाली किसी प्रमुख शक्ति से शह पाए बगैर क्या हमारा कोई भी पड़ोसी इस तरह अवज्ञा कर सकता है।

विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं होगी कि अपने पड़ोसियों तथा आसियान एवं पश्चिम एशिया समेत दूरवर्ती पड़ोसियों को किस तरह संभाला जाए बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करना भी चुनौती होगी क्योंकि वे शक्तियां अपना-अपना प्रभाव जमाने के लिए होड़ करती रहती हैं तथा किसी न किसी के जरिये यह काम करना चाहती हैं जबकि इतने बड़े आकार, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति, मानव संसाधन तथा रणनीतिक लाभ के कारण भारत ऐसी भूमिका में नहीं आ सकता। ऐसी परिस्थितियों में कोई अपने सिर पर मंडराते सायों से छुटकारा कैसे पाए.चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तो हैं ही, उसके साथ संबंध बनाए रखना बाकी सभी संबंधों की तुलना में सबसे अधिक कठिन रहा है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के जरिये तथा दरियादिली से खैरात बांटकर भारत के पड़ोस में अपना मजबूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' रणनीति उसकी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं के लिए सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहजता भरा हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मजबूत किए हैं। इसका मुकाबला करना है तो क्षेत्र में हितधारकों को उसी प्रकार का लेकिन और भी आकर्षक तथा व्यावहारिक प्रोत्साहन देना होगा।जहां तक चीन-भारत संबंध हैं तो प्रत्यक्ष तौर पर सब कुछ 'सहयोग-प्रतिस्पर्द्धा' का नमूना लग रहा है। लेकिन चीन मौके की ताक में भारत की तरफ देख रहा है[13,14] और रूस जैसे भारत के पारंपरिक साझेदारों को दूर ले जाने की कोशिश भी कर रहा है। रणनीतिक वैश्विक मंच पर जगह पाने के भारत के दावे का चीन द्वारा लगातार किया जा रहा विरोध परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के हमारे प्रयासों को विफल करता रहेगा। चीन-पाकिस्तान-रूस के बीच कुछ समय पहले हुई बैठकें तथा भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले होने के बावजूद रूस-पाकिस्तान सैन्य अभ्यास इसका उदाहरण हैं।रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता ने रूसियों को प्रकट रूप से तालिबान और अफगानिस्तान के कारण ही सही, पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने का बहाना दे दिया है। इसके संकेत कम से कम सात-आठ वर्ष से मिल रहे थे। लेकिन क्या अब मामला ऐसी जगह पहुंच गया है, जहां से वापसी नहीं हो सकती। कुछ वर्ष पहले तक यह मान लिया गया था कि रूसी प्रशासन पाकिस्तान की बातों में नहीं आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा हो चुका है और अब उसका सामना करने और उन्हें अलग करने की जरूरत है। यह भी सच है कि "भरोसेमंद और पुराने दोस्त" या "रूसी-हिंदी भाई भाई" जैसे भावनात्मक जुमलों से स्थिति पहले की तरह नहीं की जा सकती, लेकिन भारत के साथ सख्त आर्थिक रिश्ते उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकते हैं क्योंकि खनिजों तथा हीरों के अलावा सैन्य उपकरणों तथा असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए भारत अब भी उसके सबसे बड़े बाजारों में शामिल है।

कारोबार से ज्यादा समझ आने वाली भाषा कोई नहीं। इसके अलावा यदि ट्रंप-पुतिन समीकरण आगे जाकर कारगर साबित होते हैं तो चीन और पाकिस्तान दोनों के मामले में भारत के साथ रूसियों की भावनात्मक दूरी कम हो सकती है। लेकिन हम संबंधों के बारे में अपने प्रयासों के लिए हम इन कल्पनाओं के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर रूसियों के साथ कहीं भी भरोसे की कमी और गलतफहमी है तो हमें कूटनीतिक संकेतों के फेर में पड़कर मामला बिगाड़ने के बजाय सीधे उनके नेतृत्व से बात कर उसे दूर करना होगा।जहां तक अमेरिका की बात है, हालांकि भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते और भी मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों का समर्थन है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की आसक्ति और प्रतिबद्धता 'कोरे पन्ने' की तरह यानी पूर्वग्रह रहित है और अमेरिका में भारतीय समुदाय का मजबूत प्रभाव तथा राष्ट्रपति ट्रंप की कारोबारी रुख रखने वाली टीम उसे भारत की ओर केंद्रित रखने में सहायक हो सकती है। रोजगार और विनिर्माण वापस अमेरिका में लाने तथा कर ढांचों में प्रस्तावित बदलावों की नीतियों से भारत में अमेरिकी वित्तीय निवेश में कमी आने की आशंका तो है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ दिक्कत हो सकती है। यहां एक बार फिर वही

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 8, August 2017

बात आती है कि प्रतिस्पर्द्धा भरा तथा दूसरों की तुलना में अधिक फायदे एवं प्रोत्साहन भरा बाजार बने रहना हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए हमें नियमों को पिछली तिथि से लागू करने से बचना होगा क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों के मन में शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं।चीन के बढ़ते प्रभाव का उत्तर देने के लिए यदि अमेरिकी एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपनी रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत में अधिक स्थान चाहते हैं तो लघु अवधि में यह फायदेमंद हो सकता है। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंध बढ़ते रहेंगे क्योंकि अमेरिका में सैन्य-औद्योगिक तालमेल इसके पीछे प्रमुख शक्ति है, लेकिन टकराव होने पर किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगे, इसके लिए विशेष रूप से पुर्जों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। हमें भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिए या बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए।आतंकवाद विशेषक पाकिस्तान प्रायोजित आंतकी समूहों की ओर से आतंकवाद दशकों से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि (सीसीआईटी) कराने के भारत के प्रयास प्रमुख देशों की प्रतिबद्धता कम होने के कारण विफल रहे हैं। आईएसआईएस, अलकायदा और उसकी विभिन्न शाखाओं तथा चरमपंथी इस्लामी गुटों के खिलाफ लड़ाई विशेष रूप से पश्चिम एशियाई देशों के साथ खुफिया जानकारी की अधिक साझेदारी तथा सहयोग के जरिये ही करनी होगी और इसके लिए "लुक वेस्ट" नीति को "एक्ट वेस्ट" नीति में बदलना होगा, जिससे पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकी और समर्थन कम हो सकता है।चीन जैसे देश स्वयं भी आतंकवाद से पीड़ित होने के बावजूद मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाते रहेंगे और रूस का इरादा पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने का नहीं है। इससे भारत विरोधी आतंकी हरकतों को जारी रखने की पाकिस्तान की मंशा और भी मजबूत हो गई है, जिसका सामना करने के लिए व्यापक और सार्थक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन जरूरी हैं। दुनिया बदलेगी और विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों के बीच नए द्विपक्षीय समीकरण बन सकते हैं, जिनका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार, अभी जारी संघर्षों या धीमे-धीमे सुलग रहे टकरावों पर प्रभाव सकारात्मक हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। भारत को प्रासंगिक बने रहने के लिए जोखिमों की थाह लेनी होगी और अपना रुख तय करना होगा।[15]

निष्कर्ष

विदेश नीति में महत्वपूर्ण मोड़-पोखरण परमाणु परीक्षण, भारत-चीन युद्ध और गलवान घाटी संघर्ष को भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में माना गया।सबसे बड़ी अंतरराज्यीय विदेश नीति चुनौती-चीन के साथ सीमा संघर्ष को भारत की सबसे बड़ी अंतर-राज्य विदेश नीति चुनौती के रूप में देखा गया - यहां तक कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष को भी पार कर गया।आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ सीमा संघर्ष भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां बने रहे।उत्तरदाताओं के बहुमत ने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान के साथ न उलझने की भारत की विदेश नीति से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को लाभ हुआ।भारत-अमेरिका संबंध-संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता के बाद से दूसरे सबसे भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा गया था,85% उत्तरदाताओं ने सोचा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अगले 10 वर्षों में भारत का प्रमुख भागीदार होगा;83% उत्तरदाताओं ने यह भी सहमति व्यक्त की कि भारत के उत्थान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।विदेश नीति के चालक के रूप में भारतीय हित-ऐसी धारणा के लिए भारतीय हित चालक बने रहे।उदाहरण के लिए, यदि यूएस-चीन तनाव बढ़ता है, तो भारतीय युवाओं ने गुटनिरपेक्षता और तटस्थता को प्राथमिकता दी।लेकिन जब भारतीय हित दांव पर लगे तो प्रतिक्रियाएं बदल गईं: 73% ने कहा कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ गठबंधन करना चाहिए।क्षेत्रीय शक्ति का महत्व-एक बहुध्रुवीय, अधिक अनिश्चित विश्व व्यवस्था में, क्षेत्रीय शक्तियों का महत्व बढ़ रहा है।क्वाड को उत्तरदाताओं के बीच सीमित उत्साह मिला लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे कुछ सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण सकारात्मक धारणा का आनंद लिया।जापान को भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण इंडो-पैसिफिक पार्टनर के रूप में देखा गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान रहा।भारत के पड़ोसियों का महत्व-नई विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद, युवाओं ने भारत के पड़ोस को सामरिक महत्व दिया।उत्तरदाताओं का मानना था कि भारत ने अपने पड़ोस को कुशलतापूर्वक परिभाषित किया है और सभी क्षेत्रों - सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति में पर्याप्त विदेश नीति का पालन किया है।गैर-पारंपरिक और अंतरराष्ट्रीय खतरे-गैर-पारंपरिक और अंतरराष्ट्रीय खतरों को महत्वपूर्ण खतरों के रूप में देखा गया।महामारी को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा संघर्ष की तुलना में भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता था।पंचशील सिद्धांत-शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पहली बार चीन-भारतीय समझौते, 1954 में उल्लेख किया गया था और सार्वजनिक रूप से झोउ एनलाई द्वारा तैयार किया गया था।ये सिद्धांत बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बने।पंचशील समझौते पर प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधान मंत्री झोउ एनलाई द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।इन सिद्धांतों, जिन्हें पंचशील भी कहा जाता है, के रूप में सूचीबद्ध हैं:

- एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान,
- आपसी गैर-आक्रामकता,

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 8, August 2017

- एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर अहस्तक्षेप,
- आपसी लाभ के लिए समानता और सहयोग, और
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

किसी देश की विदेश नीति अक्सर लोकप्रिय धारणा से प्रेरित होती है।इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि युवा लोग विदेश नीति के लक्ष्यों को कैसे देखते हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण हितधारक हैं, भारत जैसे युवा राष्ट्र में एक और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया।[16]

संदर्भ

1. "Indian economic growth rate eases" [भारत की आर्थिक विकास दर संतोषपरक] (अंग्रेज़ी में). बीबीसी न्यूज़. ३० नवम्बर २००७. मूल से 25 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २४ जून २०१४.
2. ↑ "The Non-Aligned Movement: Description and History", nam.gov.za, The Non-Aligned Movement, 21 सितंबर 2001, मूल से 21 अगस्त 2011 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 23 अगस्त 2007
3. ↑ India's negotiation positions at the WTO (PDF), November 2005, मूल (PDF) से 13 सितंबर 2011 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 23 अगस्त 2010
4. ↑ Analysts Say India'S Power Aided Entry Into East Asia Summit. | Goliath Business News, Goliath.ecnext.com, 29 जुलाई 2005, मूल से 9 अगस्त 2011 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 21 नवम्बर 2009
5. ↑ "भारत की 37 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि है". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 12 फ़रवरी 2014. मूल से 22 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 फ़रवरी 2014.
6. ↑ "ndia has Extradition Treaties in operation with 37 countries". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 12 फ़रवरी 2014. मूल से 22 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 फ़रवरी 2014.
7. ↑ "From potol dorma to Jaya no-show: The definitive guide to Modi's swearing in" (अंग्रेज़ी में). फर्स्टपोस्ट. २६ मई २०१४. मूल से 28 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २६ मई २०१४.
8. ↑ उप्पुलुरी, कृष्ण (२५ मई २०१४). "Narendra Modi's swearing in offers a new lease of life to SAARC" (अंग्रेज़ी में). नई दिल्ली: डीएनए इण्डिया. मूल से 27 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २६ मई २०१४.
9. ↑ "ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 5 सितंबर 2014. मूल से 6 सितंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 सितंबर 2014.
10. ↑ "ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर डील पर बन गई बात". नवभारत टाईम्स. 5 सितंबर 2014. मूल से 6 सितंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 सितंबर 2014.
11. ↑ "दंगों के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं: ऑस्ट्रेलियाई PM". नवभारत टाईम्स. 5 सितंबर 2014. मूल से 6 सितंबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 सितंबर 2014.
12. ↑ भारत जापान का समुद्री सहयोग Archived 2014-09-03 at the Wayback Machine रेडियो दायेच विले (जर्मन रेडियो प्रसारण सेवा)।
13. ↑ आर्चिस मोहन - प्रधान मंत्री श्री शिंजो अबे की यात्रा : भारत - जापान संबंधों की पराकाष्ठा Archived 2016-09-12 at the Wayback Machine विदेश मंत्रालय, भारत सरकार
14. ↑ भारत-जापान व्यापार 2014 तक 25 अरब डॉलर Archived 2014-09-03 at the Wayback Machine - Indo Asian News Service, Last Updated: दिसम्बर 29, 2011
15. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 4 मई 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 फ़रवरी 2014.
16. ↑ "Amid BRICS' rise and 'Arab Spring', a new global order forms" Archived 2011-10-20 at the Wayback Machine. Christian Science Monitor. 18 अक्टूबर 2011. Retrieved 2011-10-20.